

# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी- मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या- 2025 / 80

1. घांसीलाल पुत्र स्व० भैरूलाल
  2. छीतरलाल पुत्र स्व० भैरूलाल
  3. रमेश पुत्र स्व० भैरूलाल
- जाति नई निवासीगण ग्राम डडवाडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा

- अपीलांतगण

बनाम

1. रामप्रताप पुत्र फून्दीलाल जाति मीना निवासी ग्राम डडवाडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा
2. दी स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा

-रेस्पोंडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस-1. श्री दयाराम सेन, अभिभाषक अपीलांट की ओर से ।  
2 श्री चन्द्रप्रकाश खण्डेलवाल, अभिभाषक, रेस्पों. संख्या 1 की ओर से

निर्णय

दिनांक 12.09.2025

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय सहायक कलेक्टर(मुख्यालय), कोटा जिला कोटा के प्रकरण संख्या 42A/2017 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.02.2025 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार हैं कि वादीगण अपीलांट द्वारा एक वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर कथन किया कि एक वाद, बाबत विवादित आराजी पर खातेदारी घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा पेश किया गया। वादीगण की ओर से पेश वादपत्र में निवेदन किया गया कि वादीगण पेश से काश्तकार व्यक्ति है तथा काश्तकारी करके अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। ग्राम डडवाडा (भंवरिया) तहसील लाडपुरा जिला कोटा में पुराने खसरा नम्बर 160 रकबा 7 बीघा 2 बिस्वा किस्म बंजड़ भूमि स्थित थी जिसके सेटलमेन्ट उपरान्त नये खसरा नम्बर 435 की रकबा 1.14 हैक्टर कायम किये गये। उक्त



*(Handwritten signature)*

अपील संख्या 2025/80  
घांसीलाल बनाम रामप्रताप, सरकार

आराजी पर आज से चालीस वर्ष पूर्व से जब तक वादीगण पिता स्व० भैरूलाल जी जीवित रहे, वह काबिज काशत रहे तथा उनकी मृत्यु के बाद से वादीगण लगातार बहैसियत खातेदार काबिज काशत चले आ रहे हैं तथा वर्तमान में भी वादीगण का उक्त भूमि पर कब्जा काशत है। प्रतिवादी नम्बर-1 द्वारा केम्प में गलत बयानी करके उक्त आराजी में से 6 बीघा 2 बिस्वा आराजी को अपने नाम नियमन करवा लिया तथा उसका इन्तकाल नम्बर 144 दिनांक 18.02.1978 को प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम दर्ज कर राजस्व रिकोर्ड में प्रतिवादी नम्बर 1 का नाम अंकित कर दिया गया है। विवादित आराजी पर न तो पूर्व में प्रतिवादी नम्बर 1 का कब्जा था और ना ही वर्तमान में प्रतिवादी नम्बर 1 का कब्जा काशत है। केवल कागजों में ही उसका नाम अंकित है। वास्तविक रूप से उपरोक्त आराजी पर वादीगण का अपने पिता के जीवनकाल से जब तक भैरूलाल जी जीवित रहे वह काशत करते रहे तथा उनकी मृत्यु के बाद से वादीगण -उक्त आराजी पर बहैसियत ट्रेस पास कब्जा चला आ रहा है, आराजी को अपने पुराने कब्जे के अनुसार अपने खाते दर्ज करवाने आवन्टन/नियमन करवाने के अधिकारी है। प्रतिवादी नम्बर-1 के दिल में बदनियती आ जाने के कारण वह वादीगण के कब्जे काशत में दखलन्दाजी करने लग गया है तथा जबरन भूमि पर कब्जा करने को आमादा है। इस कारण वादीगण के लिये आवश्यक हो गया है कि वह माननीय न्यायालय में वाद पेश करके उक्त भूमि में से प्रतिवादी नम्बर 1 का नाम हटवावे तथा उक्त आराजी का अपने आपको पुराने कब्जे के आधार पर खातेदार घोषित करवावे तथा प्रतिवादी नम्बर 1 के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्रदान की जावे। वाद कारण दिनांक 14.12.2010 प्रतिवादी नम्बर 1 द्वारा वादीगण के कब्जे काशत की आराजी पर जबरन कब्जा करने की चेष्टा करने की धमकी देने पर उत्पन्न हुआ। अतः वाद पेश कर निवेदन है कि वादीगण को आराजी खसरा नम्बर 160 रकबा 7 बीघा 2 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर का 435 रकबा 1.14 हेक्टर है, का खातेदार घोषित कर उक्त भूमि को वादीगण के खाते दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे। आराजी खसरा नम्बर 435 रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा का प्रतिवादी नम्बर-1 के नाम रेगुलाईज का आदेश व उसके आधार पर जो इन्तकाल नम्बर 144 दिनांक 18.02.1978 खोला गया है उसको प्रभाव शून्य घोषित किया जाकर प्रतिवादी नम्बर-1 का नाम इन्तकाल व राजस्व रिकार्ड से हटाये जाने का आदेश प्रदान किया जावे। प्रतिवादी नम्बर-1 के विरुद्ध इस आशय की निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वह वादीगण के कब्जे काशत की उपरोक्त आराजी में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करें तथा उन्हें शान्तिपूर्वक काशत करने दे तथा जबरन कब्जा नहीं कर उक्त कृत्य न तो स्वयं करे और न अपने एजेन्ट से करावें।



*Handwritten signature*

अपील संख्या 2025/80  
घांसीलाल बनाम रामप्रताप, सरकार

3. उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 27.02.2025 को वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद खारिज किए जाने की निर्णय व डिकी पारित की गई।
4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 27.02.2025 से व्यथित होकर अपीलान्त ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिकी दिनांक 27.02.2025 को खारिज फरमाया जावे।
5. अपीलांत की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना में रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।
6. विद्वान अधिवक्ता अपीलांत ने अपनी बहस में अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि निर्णय योग्य अधीनस्थ न्यायालय न्याय संचिका के सिद्धी प्राप्त तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं। निर्णय एवम डिकी जेर अपील कानून न्याय एवं तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत वाद 88, 89 व 188 आर० टी० ए० निरस्त करने में त्रुटि की है। अपीलान्त द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपना वाद सम्पूर्ण दस्तावेजी साक्ष्य व अपनी साक्ष्य से पूर्णतया प्रमाणित किया गया है जिसको नजर अन्दाज करके वादी अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज करने में त्रुटि की है। ग्राम डडवाडा (भंवरिया) तहसील लाडपुरा जिला कोटा में पुराने ख० न० 160 रकबा 7 बीघा 2 बिस्वा जिसके बाद सेटलमेन्ट के उपरान्त ख० न० 435 रकबा 1.14 हेक्टेयर कायम किया गया है। उक्त आराजी पर अपीलान्त के पिता एवम उनकी मृत्यु के बाद से अपीलान्तस का लगातार कब्जा काशत चला आरहा है और आज भी अपीलान्त काबिज काशत है उक्त तथ्य को अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्त द्वारा अपनी साक्ष्य से प्रमाणित किया है जिसका खंडन भी प्रति० की ओर से नहीं आया है इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय एवं डिकी जेर अपील पारित करने में त्रुटि की है। अपीलान्त ने गलत बयान करते हुये उक्त आराजी को अपने नाम आवंटित करवाया गया है जिसके आधार पर उसका गलत रूप में नामान्तरकरण जमाबंदी में दर्ज किया गया है। अपीलान्त द्वारा उक्त



AMG

अपील संख्या 2025/80

घांसीलाल बनाम रामप्रताप, सरकार

आवंटन आदेश के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में निगरानी पेश कर रखी है जो राजस्व मंडल में लंबित है। यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पो० का मात्र राजस्व रिकार्ड में उसका नाम अंकित होना तथा भूमि आवंटन होने का कथन करते हुये दावा वादीगण खारिज किया गया है। विवादित आराजी को वर्तमान में 8 लेन में अवाप्त किया गया है जिसके संबंध में कार्यवाही चल रही है जिसमें भी अपीलान्ट द्वारा अपनी उज्रदारी क्लेम सक्षम न्यायालय/कार्यालय में पेश किया हुआ है जो लंबित चल रहा है। अपीलांट का वादग्रस्त भूमि पर निरन्तर कब्जा काशत चला आ रहा है। वादग्रस्त आराजी पर रेस्पोडेन्ट का कोई कब्जा काशत व हक अधिकार नहीं है। अपीलांट वादग्रस्त आराजी को स्वयं के खाते दर्ज करवाने का अधिकारी है। अतः ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर अपीलांटगण को वादग्रस्त आराजी का खातेदार घोषित किया जाना आवश्यक था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 27.02.2025 में अपीलांटगण वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद खारिज किए जाने का आदेश अंकित किया है जो त्रुटिपूर्ण है। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.02.2025 निरस्त की जाकर अपीलांटगण को वादग्रस्त आराजी का खातेदार घोषित किए जाने का आदेश प्रदान किए जाने का निवेदन किया।

7. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में निवेदन किया कि विवादित आराजी हाल खसरा संख्या 435 रकबा 1.14 हैक्टेयर जिसके सेटलमेंट से पूर्व खसरा संख्या 160 है, उक्त आराजी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम नामान्तरकरण संख्या 144 दिनांक 18.02.1978 के तहत विधिवत् रूप से नामान्तरकरण संख्या 144 दिनांक 18.02.1978 के तहत विधिवत् रूप से उचित आदेशानुसार खाते दर्ज की गई है। नामान्तरकरण संख्या 144 में वर्णित आदेश को निरस्त करवाये बिना अपीलांट वादग्रस्त आराजी के सम्बंध में किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अपीलांट द्वारा प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 144 दिनांक 18.02.1978 को जिला कलेक्टर महोदय कोटा के न्यायालय में चुनौती दी गई परन्तु अपीलांट द्वारा जिला कलेक्टर के न्यायालय में प्रस्तुत की गई अपील को दिनांक 25.01.2011 को खारिज किया जा चुका है। नामान्तरकरण संख्या 144 दिनांक 18.02.1978 आज भी अस्तित्व में है। वादग्रस्त आराजी पर रेस्पोडेन्टगण का निरन्तर कब्जा काशत चला आ रहा है तथा अपीलांटगण का वादग्रस्त आराजी पर किसी प्रकार का कब्जा काशत एवं हक अधिकार नहीं रहा है। रेस्पोडेन्ट ने वादग्रस्त आराजी पर बैंक से ऋण भी ले रखा है। रेस्पोडेन्ट की भूमि के निकट अपीलांट की कोई भूमि स्थित नहीं है और ना ही अपीलांटगण का वादग्रस्त आराजी से कोई सम्बंध है। अपीलांटगण ना तो वादग्रस्त आराजी के खातेदार है और ना ही उनका वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काशत है। अतः अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद को अपीलांटगण द्वारा दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रमाणित नहीं करवाया गया है अतः अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत अपील एवं वाद खारिज किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.



*Handwritten signature*

अपील संख्या 2025/80  
घांसीलाल बनाम रामप्रताप, सरकार

02.2025 विधि सम्मत है तथा इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य है। अन्त में अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.02.2025 यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

8. हमने उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों व राजस्व रिकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद में वादीगण अपीलांटगण द्वारा वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम डडवांडा(भंवरिया) तहसील लाडपुरा की खसरा संख्या 435 रकबा 1.14 हैक्टेयर का स्वयं को खातेदार घोषित किए जाने का अनुतोष चाहा गया है। अपीलांटगण का कथन है कि वादग्रस्त आराजी पर अपीलांटगण के पिता भैरूलाल तथा उनकी मृत्यु के पश्चात स्वयं अपीलांटगण वादग्रस्त आराजी पर निरन्तर एवं निर्बाध रूप से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। वादीगण अपीलांटगण द्वारा वादपत्र की चरण संख्या 4 में किया गया अंकन इस प्रकार है- "यह कि उक्त भूमि पर न तो प्रतिवादी नं01 का कब्जा काश्त था और ना ही वर्तमान में प्रतिवादी नं01 का कब्जा काश्त है। केवल कागजों में ही उसका नाम अंकित है। वास्तविक रूप से उपरोक्त आराजी पर वादीगण का अपने पिता के जीवनकाल से जब तक भैरूलाल जी जीवित रहे वह काश्त करते रहे तथा उनकी मृत्यु के बाद वादीगण उक्त आराजी पर बहैसियत ट्रेसपास कब्जा चला आ रहा है। तथा उक्त आराजी को वह पुराने कब्जे अनुसार खाते दर्ज करवाने आवन्तन/रेगुलराइज करवाने के अधिकारी है।" अतः यह अपीलांटगण वादीगण द्वारा स्वीकृत तथ्य है कि वादग्रस्त आराजी वादीगण अपीलांटगण का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा ट्रेसपास की हैसियत का रहा है। वादग्रस्त आराजी ना तो राजस्व अभिलेख में अपीलांटगण के खाते दर्ज नहीं है और ना ही अपीलांटगण ने ऐसा कोई दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे वादग्रस्त आराजी पूर्व में अपीलांटगण वादीगण के खाते दर्ज होना प्रकट होता हो। अपीलांटगण ने वादग्रस्त आराजी में केवल कब्जे काश्त होने के आधार पर खातेदारी घोषणा का अनुतोष चाहा है। परन्तु वर्तमान विधि के अनुसार कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान किया जाना विधि सम्मत नहीं है। कब्जा मुखालफाना के सम्बंध माननीय राजस्व मण्डल के न्यायिक दृष्टांत 2015 डी.एन.जे. 2015 पेज 224 एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत 2018(3)डब्ल्यू.एल.एन पेज 114 प्रतिपादित किए गए हैं जिनके अनुसार कब्जा मुखालफाना के आधार पर वाद



4/11/25

अपील संख्या 2025/80  
घोसीलाल बनाम रामप्रताप, सरकार

गोपनीय नहीं होना माना गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2065 से 2068 के अनुसार वादग्रस्त आराजी रामप्रताप वल्द फून्दीलाल कोम मीणा सा. देह की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। अतः वादग्रस्त आराजी रेस्पोंडेन्ट की खातेदारी में दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोंडेन्ट द्वारा नामान्तरकरण संख्या 144 दिनांक 18.02.1978 की प्रमाणित फोटोप्रति पेश की है जिसमें वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 160 रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा भूमि का नियमन रामप्रताप पुत्र फून्दीलाल के पक्ष में किए जाने का अंकन है। जमाबंदी सम्वत् 2034 से 2037 के अनुसार वादग्रस्त आराजी रामप्रताप पुत्र फून्दीलाल के खाते दर्ज रिकॉर्ड है। जमाबंदी भू-प्रबन्ध सम्वत् 2038 से 2057 में रेस्पोंडेन्ट रामप्रताप वल्द फून्दीलाल का नाम गैर खातेदार के रूप में अंकित है। जमाबंदी सम्वत् 2065 से 2068 में नामान्तरकरण संख्या 289 दिनांक 19.05.2009 के द्वारा वादग्रस्त आराजी रहन मुक्त किए जाने तथा नामान्तरकरण संख्या 297 दिनांक 22.06.2009 रहन दर्ज करने का नोट अंकित है। खसरा गिरदावरी चतुर्वर्षीय सम्वत् 2065 से 2068 में खातेदार के कॉलम संख्या 5 में रेस्पोंडेन्ट का नाम अंकित है तथा फसल के कॉलम संख्या 11 में धनियों की फसल का अंकन है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में हाल अपीलांटगण की ओर से जिला कलेक्टर कोटा के न्यायालय में नामान्तरकरण संख्या 144 दिनांक 18.02.1978 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील मेमो की प्रमाणित फोटोप्रति, न्यायालय जिला कलेक्टर कोटा द्वारा अपील संख्या 49/2011 में पारित आदेश दिनांक 25.01.2011 तथा न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा संभाग द्वारा अपील संख्या 72/2011 में पारित निर्णय दिनांक 28.06.2012 की प्रमाणित फोटोप्रति संलग्न है जिनके अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांटगण द्वारा नामान्तरकरण संख्या 144 दिनांक 18.02.1978 के विरुद्ध न्यायालय जिला कलेक्टर कोटा में अपील पेश की गई है जो न्यायालय जिला कलेक्टर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 25.01.2011 द्वारा निरस्त की जा चुकी है। साथ ही अपील न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा के निर्णय दिनांक 25.01.2011 की अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.06.2012 के द्वारा खारिज की जा चुकी है। अतः जिस नामान्तरकरण संख्या 144 के आधार पर वादग्रस्त आराजी रेस्पोंडेन्ट के खाते दर्ज हुई है उक्त नामान्तरकरण संख्या 144 दिनांक 18.02.1978 आज भी अस्तित्व में है। अतः नामान्तरकरण संख्या 144 को निरस्त करवाये बिना अपीलांट वादग्रस्त आराजी के सम्बंध में किसी प्रकार के हक अधिकारों की घोषणा का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय ने भी अपने निर्णय दिनांक 27.02.2025 में वादीगण अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत वाद खारिज किए जाने का जो



*Handwritten signature*

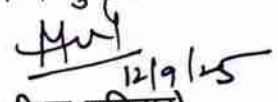
अपील संख्या 2025/80  
घांसीलाल बनाम रामप्रताप, सरकार

आदेश अंकित किया है वह विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलांत खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

9. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्त खारिज की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर मुख्यालय कोटा, जिला कोटा के प्रकरण संख्या 42A/2017 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.02.2025 यथावत रखी जाती है।

10. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलंब लौटाई जाए।

11. निर्णय आज दिनांक 12.09.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(मुरलीधर प्रतिहार)  
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा



अपील में डिक्री  
(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)  
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा  
बइजलास मुरलीधर प्रतिहार, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 2025/80

1. घांसीलाल पुत्र स्व० भैरूलाल
2. छीतरलाल पुत्र स्व० भैरूलाल
3. रमेश पुत्र स्व० भैरूलाल  
जाति नाई निवासीगण ग्राम डडवाडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा

— अपीलांटगण

बनाम

1. रामप्रताप पुत्र फून्दीलाल जाति मीना निवासी ग्राम डडवाडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा
2. दी स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा

—रेस्पोंडेन्टगण

वाद संख्या: 42A/2017

1. घांसीलाल पुत्र स्व० भैरूलाल
2. छीतरलाल पुत्र स्व० भैरूलाल
3. रमेश पुत्र स्व० भैरूलाल  
जाति नाई निवासीगण ग्राम डडवाडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा

—वादीगण

बनाम

1. रामप्रताप पुत्र फून्दीलाल जाति मीना निवासी ग्राम डडवाडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा
2. दी स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा

—प्रतिवादीगण




42A

## अपील का ज्ञापन

1. उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद संख्या 42A/2017 में न्यायालय सहायक कलेक्टर(मुख्यालय) कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.02.2025 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः उक्त अपील अपीलान्त स्वीकार फरमाई जावे ।
2. उक्त अपील तारीख 12.09.2025 को बहाजरी अपीलान्त की ओर से विद्वान् अभिभाषक श्री दयाराम सेन तथा रेस्पोजेन्ट कम 1 की ओर से विद्वान अभिभाषक श्री चन्द्रप्रकाश खण्डेलवाल के उपस्थित होने पर यह आदेश दिया जाता है कि अपीलान्त की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर(मुख्यालय) कोटा जिला कोटा के प्रकरण संख्या 42A/2017 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.02.2025 यथावत रखी जाती है।
3. इस अपील के खर्च एवं मूल वाद के खर्च पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है।
4. यह डिक्री आज तारीख 12.09.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर



  
12/9/25  
(मुरलीधर प्रतिहार)  
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा